भारतीय राजनीति में आन्तरिक उथल पुथल तथा सम्पूर्ण विश्व का राजनैतिक घटनाक्रम इस प्रकार गतिमान था कि देश में व्यापक एवं संगठित आन्दोलन के प्रारम्भ होने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप गाँधीजी ने "भारत छोड़ो आन्दोलन" प्रारम्भ किया। 1942 का "भारत छोड़ो" आंदोलन भारत के इतिहास की एक युगान्तकारी घटना थी। यूं तो 'भारत छोड़ो आंदोलन" की विधिवत घोषणा गाँधीजी द्वारा 8 अगस्त 1942 को की गई, किन्तु इस आंदोलन की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 ई. से तैयार हो रही थी। अतः कहा जा सकता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां

(1) भारतीय नेताओं द्वारा उत्तरदायी सरकार की माँग (Demand for Responsible Government by Indian Leaders)—सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ था। भारत सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केन्द्रीय विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्यों से सलाह लिए बगैर तुरन्त युद्ध में कूद पड़ी। भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया गया तथा भारतीय सेनाएं मिस्त्र, अदन और सिंगापुर भेज दी गईं। इस घटना से नाराज होकर अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने 11 में से 8 प्रान्तों से अपने त्याग–पत्र दे दिये। केवल सिन्ध, पंजाब और बंगाल में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल कार्य कर रहे थे। कांग्रेस ने सरकार से उनके युद्ध उददेश्य प्रकट करने की मांग की, किन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि संघर्ष का उददेश्य साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य उपनिवेशों का बंटवारा था।

(2) कांग्रेस के असहयोग तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की असफलता (Failure of Non-Cooperation and Individual Movements)— यद्यपि कांग्रेस अंग्रेजी सरकार को ऐसे समय जब ब्रिटेन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण काफी विषम परिस्थितियों में था, उसकी

कठिनाइयों को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहती थी, किन्तु सरकार के रवैये से क्षुब्ध होकर अगस्त 1940 में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जिन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ने भी अपनी गिरफ्तारियां दीं। इस समय तक युद्ध के मोर्चे पर ब्रिटेन की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। पर्लहार्बर पर जापानी आक्रमण, पूर्वी एशिया में उसकी बढ़ती प्रगति से ब्रिटिश सरकार घबरा उठी। सुभाषचन्द्र बोस भी जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। वर्मा में अंग्रेजों की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार और कांग्रेस दोनों एक–दूसरे के करीब आ गए। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के उद्देश्य से ''क्रिप्स मिशन'' को भारत भेजा। अमेरिका तथा चीन ने भी ब्रिटेन पर भारत की राजनैतिक समस्याओं के उचित समाधान के लिए दबाव डाला।

(3) क्रिप्स मिशन की असफलता (Failure of Cripps Mission)–23 मार्च 1942 को कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत पहुंचे। उन्होंने विभिन्न पक्षों – कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, हरिजनों, देशी नरेशों तथा उदारवादियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। इसके पश्चात् उन्होंने भारतीय समस्या को हल करने के लिए 30 मार्च को सरकार की ओर से कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जो 'क्रिप्स प्रस्ताव' के नाम से प्रसिद्ध है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव निम्नलिखत थे–

1. एक नये भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसे स्वशासित उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का मानना था कि विभिन्न राज्यों और प्रान्तों को भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। वह किसी घरेलू या बाह्य सत्ता के अधीन नहीं होगा और यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध–विच्छेद कर सकेगा।
2. युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद एक संविधान–निर्मात्री–संस्था का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रिसायतों के प्रतिनिधि होंगे।
3. युद्धोपरांत बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा कि कोई भी भारतीय प्रान्त यदि वह चाहे तो भारतीय संघ से बाहर रह सकेगा और इस विषय पर ब्रिटेन से सीधे बातचीत कर सकेगा।

क्रिप्स के घोषणा–पत्र को लगभग सभी राजनैतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भविष्य के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। गाँधीजी ने क्रिप्स प्रस्तावों की उपमा एक **''दिवालिया बैंक के नाम काटे गए' उत्तर दिनांकित चैक'** से दी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को यह कहकर अस्वीकार कर

1. *Post - dated cheque*

दिया कि इसमें साम्प्रदायिक आधार पर देश–विभाजन की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में पाकिस्तान और अलग संविधान सभा के निर्माण के अभाव में उसे अस्वीकार कर दिया।

दलित वर्गों, सिक्खों भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लों–इंडियन ने अपने–अपने समुदायों के लिए रक्षा उपायों की मांग रखी। इस प्रकार " क्रिप्स मिशन" भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा।

(4) आर्थिक कठिनाइयां (Economic Difficulties)—भारत पर जापान के संभावित आक्रमण की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने अतिरिक्त अंग्रेजी व अमेरिकी सेनाएं तैनात कर दी किन्तु इसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देश में खाद्य वस्तुओं की कीमतें आकाश छूने लगीं। कालाबाजारी के कारण खाद्य आपूर्ति की कमी हो गई। बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग की स्थिति काफी शोचनीय हो गई और इस वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना प्रबल हो गई।

(5) अंग्रेजों के प्रति विश्वास में कमी (Lock of Faith Towards Britishers)—भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर अविश्वास था, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय दिये गये वचनों का पालन नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को झूठे आश्वासन देती रही, किन्तु वास्तविक शक्ति देने का प्रयास कभी नहीं किया। चर्चिल ने दिसम्बर 1941 में स्पष्ट रूप से कहा था कि **"मैं ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ।"**[1] इसके अतिरिक्त उसने घोषणा की कि "एंटलांटिक चार्टर" में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत पर लागू नहीं होगा। इन सभी कारणों से भारतीयों में निराशा की भावना गहराने लगी और गाँधी ने अब उग्रतापूर्वक सोचना आरम्भ कर दिया।

"अंग्रेजों भारत छोड़ो" का विचार गाँधी के मस्तिष्क में जमने लगा और उन्होंने उसे **"हरिजन"** नामक लेख में लिखा। उनके दिमाग में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि अंग्रेजों को अब तुरंत भारत छोड़ देना चाहिये, क्योंकि भारत पर जापानी आक्रमण को भारत में उनकी उपस्थिति के कारण बढ़ावा मिल रहा था। उनका विचार था कि इस समय शांत रहना या अन्याय सहना कायरता होगी और अब अवश्य सरकार के विरूद्ध कोई कदम उठाना चाहिये चाहे उसका युद्ध पर किसी प्रकार का प्रभाव क्यों न पड़े।

(6) पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण (Atmosphere of Terror in East Bengal)—अंग्रेजों ने जापान के संभावित आक्रमण को ध्यान में रखते हुए उसे पूर्वी बंगाल में ही रोकने के प्रयत्न किये। बंगाल की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया गया और हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की आजीविका को नुकसान पहुँचाया। सरकार ने उन्हें राहत पहुँचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इस घटना के कारण भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा की भावना बढ़ने लगी।

(7) बर्मा के शरणार्थियों के प्रति अंग्रेजों का भेदभाव एवं दुर्व्यवहार (Descrimination and Misbehaviour by the English People with Refugee's from Burma)—बर्मा पर जापान के आक्रमण के बाद बर्मा से भारत आने वाले भारतीय और अंग्रेज शरणार्थियों के यात्रा–प्रबन्ध में सरकार ने रंगभेद तथा जातिभेद जैसी नीति का परिचय दिया। वहां से भारतीयों तथा अंग्रेजों के भारत लौटने के लिए अलग–अलग मार्गों की व्यवस्था की गई। अंग्रेज शरणार्थियों के लिए रास्ते में खाने तथा आराम करने का प्रबन्ध था, किन्तु भारतीयों के लिए नहीं। अंग्रेजों की इस भेदभावपूर्ण नीति से भारतीयों का अंग्रेजों से विश्वास टूट गया।

(8) अंग्रेजों की सैनिक क्षमता में अविश्वास (Non Confidence in the Military Power of the English)—द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की जापान के हाथों निरन्तर पराजय, सिंगापुर मलाया तथा बर्मा आदि पर जापान के अधिकार से लोगों में अंग्रेजों की सैनिक क्षमता के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया। गाँधीजी को भी विश्वास होने लगा कि यदि भारत अंग्रेजों के अधिकार में रहा तो जापान भारत पर भी अवश्य आक्रमण करेगा। उन्होंने लिखा – **"अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।"**[1] इसके अतिरिक्त इस समय सारे देश में घोर निराशा का वातावरण छाया हुआ था। ऐसे समय में गाँधी जनता में उत्साह जाग्रत करने के लिए आन्दोलन का एक कार्यक्रम प्रदान किया।

वर्धा प्रस्ताव (Verdha Proposal)

14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में हुई। इससे गाँधीजी द्वारा पुनः–आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। वर्धा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद जनता में यह भावना जाग्रत हुई कि कांग्रेस की ओर से जल्द से जल्द जनांदोलन की घोषणा की जायेगी, किन्तु कुछ सोच कर कांग्रेस ने ऐसी घोषणा नहीं की। **सरदार पटेल ने कहा, "इस बार का आंदोलन थोडे दिनों का , किन्तु बड़ा भयानक होगा।"**[2] डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किये। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू ने कहा कि **"हम आग के साथ खेलने जा रहे है, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, लेकिन हम क्या करें, विवश है।"**[3] इस प्रकार कांग्रेस के उच्चकोटि के नेताओं द्वारा जनता को यह आभास होने लगा कि कांग्रेस की ओर से शीघ्र ही एक भीषण आंदोलन प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार भी कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया एवं संभावित जनांदोलन को कुचलने के लिए पहले से तत्पर थी।

कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन और भारत छोड़ो आन्दोलन

(Bombay Assembly of Congress and Resolution of Quite India Movement)

7 अगस्त 1942 को कांग्रेस महासमिति की बैठक बम्बई में हुई और 8 अगस्त को महात्मा गाँधी ने समिति के समक्ष अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया था कि "भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अन्त भारत के लिए तथा मित्र राष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य , स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है।

"......... अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता को हटा लिये जाने की मांग दोहराती है।.......... आधुनिक साम्राज्यवाद का केन्द्रबिन्दु भारत अब इस समस्या का मुख्य विषय बन गया है। .... अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश के प्रमुख राजनैतिक दलों तथा वर्गों से एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया जायेगा, जिसका मुख्य उददेश्य अपनी सैनिक तथा अहिंसात्मक शक्ति के प्रयोग से विदेशी आक्रमण के विरूद्ध देश की सुरक्षा करना होगा।"

यह उम्मीद की जाती थी कि अंग्रेज भारत को छोड़कर आसानी से नहीं जायेंगे। अतः एक जनांदोलन चलाने का निश्चय किया गया, जिसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई। इस अवसर पर गाँधीजी ने एक बहुत अधिक प्रभावशाली भाषण दिया। कांग्रेस महासमिति को दिये गये भाषण में उन्होंने घोषणा की, कि यह संघर्ष मेरे जीवन का अन्तिम संघर्ष होगा और उन्होंने जनता को 'करो या मरों' का इतिहास प्रसिद्ध सन्देश दिया, जिसका तात्पर्य यह था कि भारतीय जनता स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु हरसंभव प्रयास करे, लेकिन यह लड़ाई खुली तथा अहिंसक होगी, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं होगा। महात्मा गाँधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वायसराय से मिलेंगे और मित्र राष्ट्रों से अपील करेंगे, लेकिन सरकार ने उन्हें इसके लिए समय नहीं दिया। 9 अगस्त को महात्मा गाँधी और कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्दवल्लभ पंत, आसफ अली, अबुलकलाम आजाद एवं पट्टाभिसीतारमैया को अंग्रेजी सरकार ने कैद कर लिया और कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम (Programme of Quite India Movement)

प्रथम चरण (First Stage) –

1. आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन।
2. नमक बनाना।
3. गैर कानूनी सभाओं की सदस्यता।

द्वितीय चरण (Second Stage)–

1. वकील वकालत छोड़ दें।
2. जज अदालत का बहिष्कार करें।
3. विद्यार्थी विद्यालय त्याग दें।
4. सरकारी कर्मी पद छोड़ दें।

तृतीय चरण (Third Stage)–

1. मजदूरों की हड़ताल।

चौथा चरण (Fourth Stage)–

1. विदेशी कपड़ों का बहिष्कार व होली जलाना।
2. शराब की दुकानों पर धरना व बहिष्कार।
3. विदेशी मुद्रा में व्यापार का बहिष्कार।

पंचम चरण (Fifth Stage)–

कुछ विषयों पर न रोक लगाई जाए, नहीं बढ़ावा दिया जाए जैसे–

1. गाड़ी रोकना।
2. बिना टिकट यात्रा।
3. टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन काटना।

छठा चरण (Sixth Stage)–

1. कर न देना।
2. फौजों को रोकना।
3. आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित न करना।

गाँधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 13 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, जो निम्नलिखित था–

1. सारे देश में हड़ताल का आयोजन, जो कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाने के विरुद्ध होगी।
2. देश भर में भारत छोड़ो का संदेश पहुँचाने हेतु सभाएं होगी, जिन पर रोक का जनता विरोध करेगी।
3. नमक बनाने पर किसी भी प्रकार की रोक का विरोध होगा।
4. हमारा उद्देश्य देश भर में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाना है।
5. विद्यार्थी मुख्य भूमिका निभाएंगे तथा बंदी नेताओं का स्थान लेंगे।
6. सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दें अथवा सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करें।
7. फौजी पहले खुद को कांग्रेसी समझें एवं आत्मा को कष्ट पहुँचाने वाले आदेशों का उल्लंघन करें।
8. राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए।
9. नारियाँ अहिंसक आंदोलन में भाग लें।
10. करो या मरो का नारा अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, इससे संघर्ष में बलिदान देने की भावना बहुत प्रबल हो जाएगी।
11. सभी हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें भाग लें।
12. गाँधी के बंदी होने के बाद हर भारतीय आंदोलन का नेतृत्व करें।
13. यदि लाखों लोग चरखा चलाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सफल [illegible]

आन्दोलन का प्रारम्भ (Start of The Movement)

प्रिय नेताओं की गिफ्तारी ने जनता को अनियंत्रित एवं उत्तेजित कर दिया। नेताओं तथा संगठनों के अभाव में आंदोलन का नेतृत्व युवकों ने संभाला। नेताओं तथा संगठनों के अभाव के कारण उन्हें नियंत्रित करनेवाला कोई नहीं था। आंदोलन अहिंसक नहीं रहा। जनता ने हिंसा व विरोध का सहारा लिया।

जगह–जगह हड़तालें एवं प्रदर्शन किए गए। **"करो या मरो"** के नारों से देश गूंज उठा। अंग्रेजों के विरोध में जुलूस निकाले गए। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग चारों ओर होने लगी। कारखानें, स्कूल तथा कॉलज बन्द हो गए। अहमदाबाद, बंगलौर तथा सहारनपुर में फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से युद्ध का सामान बनना बंद हो गया, जिससे युद्ध–प्रयासों पर प्रभाव पड़ा। जनता ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों, थानों डाकघरों तथा रेल्वे स्टेशन पर हमले किए। फौजी गाड़ियाँ जलाई गई। संचार–साधनों टेलीफोन, टेलीग्राफों को नष्ट किया गया। सरकारी इमारतों को जला दिया गया। अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने अस्थायी नियंत्रण कायम कर लिया और समानांतर सरकारें स्थापित कर लीं। इन क्षेत्रों को पुनः जीतने में सरकार को अनेक सप्ताह लगे। यू तो सम्पूर्ण देश ने इस आंदोलन में भाग निया , किन्तु सबसे अधिक यू.पी., बिहार, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई आदि सबसे आगे थे। 1942 के आंदोलन के मुख्य आधार छात्र, मजदूर एवं किसान थे भारतीय उच्च वर्ग और नौकरशाही ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनी रही।

सरकार ने 1942 के आंदोलन को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। उसने दमन की सारी सीमाओं को तोड़ डाला। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी का प्रयोग किया गया तथा कैदियों को कठोर यातनाएं दी गई। जनता पर पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का आतंक छा गया। सेना ने अनेक शहरों पर नियंत्रण कर लिया। पुलिस और सेना की गोलियों से 10 हजार से अधिक लोग मारे गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। विद्रोही गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए तथा ग्रामीणों की कोड़ों से पिटाई की गई। देश में आतंक के शासन की स्थापना कर सरकार ने लगभग तीन महीने के अंदर आंदोलन को दबा दिया किन्तु भूमिगत आंदोलन चलता रहा। जयप्रकाश नारायण, अरूणा आसफअली और राममनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने उसका मार्गदर्शन किया। इस आंदोलन के सम्बन्ध में बिपिचन्द्र, अमलेश त्रिपाठी तथा वरूण डे का मत है कि **"अलग–अलग व्यक्तियों के आक्रोश भरी चुनौती के रूप में जो कार्यवाही शुरू की गयी, वह बढ़कर एक आदोलन में बदल गई और फिर आंदालन ने विद्रोह का रूप ले लिया"**[1]

आंदोलन में लोगों को सुभाषचन्द्र बोस के कार्यों से काफी प्रेरणा मिली। सुभाषचन्द्र बोस जापान के साथ मिलकर आजाद हिन्द फौज का गठन कर चुके थे और बर्मा की तरफ से

---

1 *"The Action intiated by indivisduals by way of angry challenge turned into a massive movement and the movement resulted into a great revolt."*

Bipinchandra , Amlesh Tripathi and Varun De.

भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। कहा जा सकता है कि 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन सच्चे अर्थों में स्वचालित जनांदोलन था। इस आंदोलन का श्रेय विद्यार्थियों, श्रमिकों, देश की युवा पीढ़ी तथा कुछ समाजवादी नेताओं को दिया जा सकता है।

आंदोलन के प्रति भारत के अन्य दलों की भूमिका (Role of Other Parties Towards Movements)

मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन की निन्दा करते हुए मुस्लिमों को इस मे भाग लेने से मना किया। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण सरकार के प्रति **'उदार तटस्थता'** का रहा। अम्बाप्रसाद **के अनुसार "समस्त कांग्रेसी नेतृत्व के जेल में जाने के कारण** लीग ने उस **समय का इस्तेमाल विभिन्न मुस्लिम बहुल क्षेत्रों मे अपनी स्थिति मजबूत करने में** लगाया, **जिससे** पाकिस्तान **के निर्माण हेतु अभियान को सुदृढ़ता मिली, जो कि उस नाजुक** समय **का सबसे ज्यादा** खतरनाक **निर्णय था।"**[1]

हिन्दू महासभा के प्रधान सावरकर ने यद्यपि सरकार की आलोचना की तथापि आंदोलन में उन्होंने हिन्दुओं को भाग लेने से मना किया, बाद में हिन्दू महासभा का रवैया बदल गया। 31 अगस्त 1942 के प्रस्ताव में इसने पूर्ण स्वतंत्रता तथा भारत में राष्ट्रीय सरकार की मांग की। सर तेजबहादुर सप्रू जैसे उदारवादी नेता ने भी इस आंदोलन को अच्छा नहीं माना। हरिजन नेता अम्बेडकर, एंग्लो इंडियन समुदाय के एंथोनी, अकाली पार्टी तथा भारतीय ईसाइयों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया।

किन्तु 1942 के आंदोलन में सबसे शर्मनाक भूमिका साम्यवादी दल की रही। भारत के साम्यवादी दल ने युद्ध को साम्राज्यवादी बताते हुए पहले उसकी आलोचना की किन्तु जब हिटलर(जर्मनी) ने रूस पर आक्रमण कर दिया और सोवियत रूस मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में कूद पड़ा तो साम्यवादी दल ने इसे जनता के युद्ध की संज्ञा देते हुए भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहा। साम्यवादी दल ने **"भारत छोड़ो आंदोलन"** की निन्दा की। साम्यवादी नेताओं से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। साम्यवादी दल ने मुस्लिम लीग के साथ सांठ–गांठ कर कांग्रेसी नेताओं की अनुपस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि 1937 के चुनाव में जो मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, अब पांच प्रान्तों में पदासीन हो गई। साम्यवादी दल ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का भी समर्थन किया। साम्यवादियों की इस नीति के कारण वे राष्ट्रीय आंदोलन की मूलधारा से दूर हो गये, उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा तथा 1942 के आंदोलन के समय की गई कार्यवाहियों को देशद्रोह माना गया। इस प्रकार कांग्रेस ही इस समय एकमात्र ऐसी संस्था थी, जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलने के लिए जनांदोलन कर रही थी।

आंदोलन की असफलता के कारण (Reasons for The Failure of Movement)

"भारत छोड़ो आंदोलन" में जनता ने बड़े साहस एवं उत्साह से भाग लिया। प्रारम्भ में इसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, किन्तु अन्त में सरकार के कठोर दमनचक्र के कारण तथा नेतृत्व के अभाव में आंदोलन सफल नहीं हो सका। इस आंदोलन की असफलता के निम्नलिखित कारण थे –

(1) सरकार ने आंदोलन का दमन बहुत कठोरता के साथ किया। आन्दोलनकारियों के साथ क्रूर तथा पाशविक व्यवहार किया गया। फलतःदेश में आतंक का वातावरण छा गया।

(2) किसी भी जनआंदोलन की सफलता पर्याप्त तैयारी पर निर्भर करती है, किन्तु 1942 का "भारत छोड़ो आंदोलन" बिना किसी पूर्व निश्चित योजना तथा कार्यक्रम के अभाव में ही प्रारम्भ हो गया।

(3) 8 अगस्त 1942 को आन्दोलन का प्रस्ताव पास करने के तुरन्त बाद 9 अगस्त की सुबह गाँधीजी सहित कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया फलतःआंदोलनकारियों को उचित नेतृत्त्व प्राप्त नहीं हो सका। उचित नेतृत्त्व के अभाव में आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके लिए देश तैयार नहीं था।

(4) आन्दोलन को साम्यवादियों, मुस्लिम लीग तथा दलित वर्ग का समर्थन नहीं मिला। साम्यवादियों और मुस्लिम लीग के सरकार के साथ हुए गठबंधन के कारण भी इस आंदोलन को गहरा धक्का लगा।

(5) देशी रियासतों के नरेशों, सेना, उच्च अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति वफादार रहे जो आन्दोलनकारियों की गुप्त सूचनाएँ सरकार के पास पहुँचाते थे, इसलिए सरकार को आन्दोलन कुचलने में सफलता मिल गई।

(6) सरकार से मुकाबले के लिए आन्दोलनकारियों के पास साधन एवं शक्ति का अभाव था इसलिए आन्दोलन असफल रहा।

आन्दोलन का महत्व (Importance of The Movement)

(1) 1942 का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध किया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा देशव्यापी विद्रोह था। यह आंदोलन जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करने में पूर्णतया सफल रहा। इसी कारण जयप्रकाश नारायण ने इसकी तुलना फ्रांस तथा रूस में हुई क्रान्तियों से की। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने कहा है–"**यह अगस्त क्रांति निरंकुशता तथा अत्याचार के विरूद्ध जनता का विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस के बास्तील के पतन और रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता में उत्पन्न नवीन विश्वास का द्योतक था**"[1]